Employee's share is equity for public sector

2339. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Standing Conference on Public Enterprises has recommended a 5 per cent share in equity for public sector employees; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) Government have appointed a Committee to suggest modalities of further disinvestment. The recommendations of the Standing Conference of Public Enterprises have been conveyed to the Committee for its consideration. Final Report of the Committee is awaited.

कपड़ा मिल मशीनरी का निर्यात

2240. **श्री रणजीत सिंह :**
श्रीराम जेठमलानी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपड़ा मिल मशीनरी उद्योग में कपड़ा मिल मशीनें निर्यात करने की पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इन मशीनों का आधुनिकीकरण करके इस क्षमता में वृद्धि की जा सकती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान कपड़ा मिल मशीनों का निर्यात किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इन वर्षों में निर्यात की गई मशीनों का अलग-अलग मूल्य कितना है ;

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है ;

(च) क्या यह भी सच है कि कपड़ा मिल मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उदार शर्तों पर ऋण देना बन्द कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान क्रमशः 156 करोड़ रु० और 125 करोड़ रु० की कपड़ा मिल मशीनों का निर्यात हुआ है ।

(ङ) इन मशीनों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना तथा ई पी सी जी योजना के तहत पूंजीगत माल के आयात के अलावा तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन पूंजीगत माल, विदेशी प्रौद्योगिकी, रेखाचित्रों और डिजाइनों के आयात की अनुमति देती रही है । सरकार ने औद्योगिक तथा आयात-निर्यात संबंधी उदारीकृत नीतियां भी आरंभ की हैं जिनमें लाइसेंसीकरण प्रक्रियाओं, मात्रा संबंधी प्रतिबंधों और विनियमकारी एवं भेदमूलक अन्य नियंत्रणों को पर्याप्त रूप से समाप्त किया गया है ।

(च) और (छ) कपड़ा मिल मशीनरी सहित चुनिंदा उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए नवम्बर, 1976 से एक उदार ऋण योजना लागू थी । सभी